want to get them through. And, therefore, there was also a statement made by our Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi that irrigation should be brought under Central List, so that all these inter-state disputes which arise, and which put impediments in the process of implementation, can be removed. Since this Council has been set up, I would like to know whether Government is seriously thinking, as a matter of policy, of putting irregation exclusively in the Central List, so that all these disputes which come in the way of irrigation projects, can be settled very expeditiously.

SHRI Z.R. ANSARI : At present there is no proposal to bring irrigation under Central List.

मध्य प्रदेश का विदेशी सहयोग के साथ मत्स्य पालन विकास का प्रस्ताव

605. **श्री केयूर भूषण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने डेनमार्क सरकार से मत्स्य पालन विकास के लिए प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिले लिए जायेंगे ;

(ग) क्या डेनमार्क सरकार ने योजना को अपनी मंजूरी दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक हाथ में ले ली जायेगी ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) 1. Gawalior
2. Datia
3. Morena
4. Bhind
5. Shivpuri
6. Guna
7. Tikamgarh
8. Sagar
9. Chhatarpur
10. Hoshangabad
11. Raisen
12. Bhopal
13. Sehore
14. Mandsaur

(c) and (d). Proposal is under consideration of the Government of Denmark.

श्री केयूर भूषण : कब इस योजना को आप ले रहे हैं और कब यह पूरी होगी ? मत्स्य पालन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि से सर्वसाधारण तक पहुंचने के लिए यह अनाज से भी ज्यादा महत्व की है। जहां पर काम यह चल रहा है वहां अन्तर्प्रदेशीय मत्स्य परियोजना के सात जिले क्रमशः शिवपुरी, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर तथा राजनन्दगांव लिए गए हैं। वहां जो मछली पालन का काम हो रहा है, उसका लाभ नीचे के लोगों को मिल नहीं पाता, बीच के बिचौलिये उसको ले जाते हैं। विचौलिये यह लाभ न कमा पाएं और सीधे नीचे के लोगों को, आदिवासियों, हरिजनों और गरीबों को ही लाभ मिल सके, इसके वास्ते आपके पास कोई योजना है ? ऐसी कोई योजना है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं वे भी इसको लागू कर सकें, जिन के पास पांच सात एकड़ जमीन है और उस में से एक या आधा एकड़ में तालाब बना सकें और मत्स्य पालन कर सकें, उसके वास्ते कुछ विशेष सुविधा देने की आपके पास कोई योजना है ?

SHRI R. V. SWAMINATHAN : This question is regarding Danish help for the scheme. It concerns Danish Government. But regarding the other points which the Hon. Member has raised, Government has got a proposal to help small farmers, marginal farmers, Adivasis etc.—to help them in pisciculture.

श्री केयूर भूषण : ठेकेदारों से और बिचौलियों से गरीब लोगों को बचाने की आपके पास इस योजना के अन्दर कोई योजना है ताकि किसान को सीधे इस योजना का लाभ मिल सके। अभी जो तालाब हैं वे ठेके से दे दिए जाते हैं और किसानों को उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ठेकेदारों को खत्म करने की कोई योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : इस योजना के तहत छोटे किसानों को, गांवों की पंचायतों को और फिशरीज डवलपमैंट कारपोरेशन जो मध्य प्रदेश का है उसको लाभ पहुँचाना, उद्देश्य है। कारपोरेशन के जरिये से काम किया जाएगा मछली पालन को बढ़ाने का। जो बड़े रिजरवायर हैं उनमें कोआप्रेटिव्ज को ठेका देकर उनकी आमदनी बढ़ाने की बात है। पंचायतों या इंडिविजुअल्स के जो छोटे-छोटे टैंक या तालाब हैं गांवों में उनको मदद देना भी उद्देश्य है। बिचौलिये अगर मछलियां खरीद कर ले जाएं और उस में लाभ कमा लें तो उसका इलाज तो एक ही है कि हम कारपोरेशन के जरिये मछलियां बेचने का, मार्किटिंग का इन्तजाम अच्छा करें और वह भी इसके अन्दर शामिल है। कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी स्कीम इसमें शामिल है। यह प्रोजेक्ट हमारे पास 6 जनवरी को एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री में मौसूल हुआ था। 18 जनवरी को हमने इसको एप्रूव कर दिया। इससे ज्यादा जल्दी कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं होता। एक फरवरी को यह डिपार्टमैंट आफ इकोनोमिक एफेयर्ज से भी निकल कर डेनिश गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। एक महीने के अन्दर-अन्दर यह प्रोजेक्ट मन्जूर कर के, एप्रूव कर के डेनिश गवर्नमैंट के पास पहुँचा दिया गया। हम इन्तजार कर रहे हैं इसका क्या फैसला होता है। 14 जिले इसमें कवर्ड हैं। 6 जिले मध्य प्रदेश के वर्ल्ड बैंक का मछलियों का प्रोजेक्ट है उसमें कवर्ड हैं जिस में रायपुर जिला शामिल है उसमें पहले का जिस प्रकार का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मिडिलमैन से बचाने के लिये और मछलियों की पैदावार बढ़ाने, मारकेटिंग का बन्दोबस्त करना, गरीब आदमियों को फायदा पहुँचाना यही इसका मकसद है। अगर इसमें कोई कमी है और माननीय सदस्य खासतौर से हमें बतायें और क्या बेहतर इन्तजाम हो सकता है तो हम तैयार हैं।

Protection of Wild Life

\+

*607. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR :
SHRI RAJESH KUMAR SINGH :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to lay a statement showing :

(a) the steps taken by Government to ensure the protection of Wild Life during the past 3 years including the current financial year ; and

(b) whether any Sanctuaries have also been set up during this period, and if so, the names of the places where such Sanctuaries exist or are proposed to be set up in the near future (Statewise) ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOP-